'इतने कम समय में 7 लाख करोड़ रूपए के एमओयू ज़मीन पर उतरे, बहुत बड़ी उपलब्धि है'

गृह मंत्री अमित शाह ने 4 लाख करोड़ रूपए के एमओयू का भूमि पूजन किया व कानून प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

जयपुर, 13 अक्टूबर। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास को गति देने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अन्तर्गत बेहतरीन काम किया है। समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हुए, जिनमें से तीन लाख करोड़ के एमओयू का कार्य पूर्व में धरातल पर शुरू हो चुका है। वहीं, आज लगभग चार लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू से जुड़ी योजनाओं का भूमि पूजन हुआ है। शाह ने कहा कि हम जो कहते हैं, वो करते हैं। मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में इतने कम समय में 7 लाख करोड़ रुपये के एमओयू जमीन पर उतरे हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जे ई सी सी सीतापुरा में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित भव्य प्रदर्शनी 'नव विधान : न्याय की नई पहचान' का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रदर्शनी का गहनता से अवलोकन किया तथा पूरी प्रक्रिया का लाइव डैमो देखा।

अमित शाह ने सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में 9 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया।

उन्होंने प्रदेश के लगभग 40 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 240 करोड़ रुपये एवं दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के 364 करोड़ रुपये की राशि का हस्तान्तरण किया।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

- केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल समिट के अंतर्गत बेहतरीन कार्य के लिए मुख्यमंत्री व उनकी टीम की प्रशंसा की।
- मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि नये कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस विभाग, न्यायिक अधिकारियों व प्रशासनिक तंत्र को व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इन नए कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के क्रम में, पुलिस विभाग, न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र को इन नए कानूनों का व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि, ये तीन नए कानून स्वतंत्र भारत के इतिहास में क्रांतिकारी कदम हैं। पीड़ितों के अधिकारों को इन कानूनों में प्राथमिकता दी गई है, जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय और सम्मान मिल सकेगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी इन कानूनों में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इन नए आपराधिक कानूनों के अन्तर्गत नियम और अधिसूचना जारी करके इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। ये नए कानून केवल दण्ड देने के लिए नहीं, बल्कि समाज को राह दिखाने का माध्यम बनेंगे।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा, विधि मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद मदन राठौड़, केन्द्रीय गृह सचिव गोविन्द मोहन, मुख्य सचिव सुधांश पंत, एनसीआरबी निदेशक आलोक रंजन आदि उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़ी संख्या में पुलिस कार्मिक भी उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़े।

अमेरिका व चीन में ट्रेड वॉर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चीन के कब्ज़े में थे, अपनी जगह बना सकता है। भारत के कई उद्योग अभी से इस अवसर को समझ रहे हैं। वस्त्र और परिधान क्षेत्र, जो देश के सबसे बड़े रोज़गार देने वाले क्षेत्रों में से एक है, को अमेरिकी ऑर्डरों में तेज़ वृद्धि देखने को मिल सकती है, खासकर उन श्रेणियों में, जहाँ अब तक चीन का दबदबा था।

खिलौने और जूते-चप्पल बनाने वाले उद्योगों को भी फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि सस्ते माल की श्रेणी में चीन की बढ़त अब कमज़ोर होती दिख रही है। भारतीय निर्यातक मनु गुप्ता ने बताया कि "टारगैट" जैसे प्रमुख अमेरिकी खुदरा विक्रेता पहले से ही नई उत्पाद श्रृंखलाओं के लिए भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क कर चुके हैं। इसी तरह, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण, जैसे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और छोटे घरेलू सामान बनाने वाले उद्योगों को भी नए ऑर्डर मिलने की संभावना है, क्योंकि अमेरिकी इम्पोर्टर अब चीनी फ़ैक्ट्रियों के विकल्प तलाश रहे हैं। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी, जैसे-जैसे चीन दुर्लभ धातुओं और संबंधित तकनीकों के निर्यात को सीमित कर रहा है, भारतीय सौर पैनल और पवन टरबाइन पुर्ज़े बनाने वाली कंपनियाँ भी अपनी जगह मज़बूत कर सकती हैं।

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह गुणवत्ता, स्थिरता और समय पर आपूर्ति के मानकों से कोई समझौता न करे। अगर भारतीय निर्माता अंतरराष्ट्रीय स्तर की विश्वसनीयता साबित कर पाए, तो वे मौजूदा टैरिफ अशांति से कहीं आगे तक इन लाभों को सुरक्षित रख सकते हैं।

जहाँ, भारत एक विजेता के रुप में उभर सकता है, वहीं, अन्य अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह व्यापार युद्ध मेक्सिको, कैनडा, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसी अर्थव्यवस्थाओं की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकता है, क्योंकि ये देश चीनी मध्यवर्ती वस्तुओं (इन्टरमीडियरी गुड्स) पर बहुत अधिक निर्भर हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जी.टी.आर.आई.) की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि इलेक्ट्रिक वाहन पुर्ज़ों, विंड टरबाइन और सेमीकंडक्टरों की वैश्विक कीमतें तेज़ी से बढ़ सकती हैं, जिससे दुनिया भर में मँहगाई का दबाव और बढ़ जाएगा। भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में 131.84 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिससे अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है और भारत के कुल निर्यात का लगभग पाँचवाँ हिस्सा अमेरिका को जाता है। मौजूदा टैरिफ वॉर ने इन संबंधों को और मज़बूत करने का अवसर दिया है। दोनों देश जब एक नए द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं, तो अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखला में भारत के शामिल होने की प्रक्रिया और तेज़ हो सकती है, खासकर तब, जब अमेरिकी कंपनियाँ चीन के विकल्प के रुप में राजनीतिक रूप से स्थिर और कम लागत वाले विकल्पों की तलाश में हैं।

अगर भारत इस मौक़े का पूरा लाभ उठाते हुए निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाए, बंदरगाहों का ढाँचा सुधारे और निर्यातकों को त्वरित ऋण उपलब्ध कराए, तो अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध भारत के लिए एक बड़ा व्यापारिक वरदान साबित हो सकता है, जो उसके निर्यात क्षेत्र को नया रूप देगा और उसे विश्वसनीय वैश्विक मैनुफैक्चरिंग पार्टनर के रूप में स्थापित करेगा।

अब एनडीए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संभावना है और इसके सदस्य भाजपा या अन्य दलों में शामिल हो जाएंगे। हालांकि, पिछले दो दशकों की सत्ता विरोधी लहर (एंटी-इन्कंबेंसी) के बावजूद, नीतीश कुमार की महिला मतदाताओं और अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) में अब भी मजबूत पकड़ है। बड़ी सम्भावना इस बात की भी है कि यदि यह धारणा मजबूत होती है कि कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो इन वर्गों का एनडीए से मोहभंग हो सकता है। बिहार की राजनीति के अनुभवी एवं चतुर खिलाड़ी नीतीश कुमार ने कई बार विपरीत परिस्थितियों से वापसी की है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि आगे चलकर वे कौन-सा ट्रम्प कार्ड खेलेंगे।

सीट शेयरिंग की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुनाव आयोग ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में मतदान की घोषणा की है जो 6 और 11 नवंबर को होगा। पहले चरण के नामांकन 6 अक्टूबर से और दूसरे चरण के 13 अक्टूबर से शुरू हुए। लेकिन प्रचार शुरू होने से पहले ही एनडीए को खुले विद्रोह से जूझना पड़ रहा है।

एक नाटकीय घटनाक्रम में, जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री जय कुमार सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री ललन कुमार सिंह पर टिकट बेचने और वफादार कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पार्टी की आत्मा को निजी लाभ के लिए नीलाम किया जा रहा है। नेतृत्व ने गठबंधन गणित के नाम पर अपने कैडर से विश्वासघात किया है।

इधर, भाजपा में भी असंतोष की लहर उठी। केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुले मंच से केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की आलोचना की, उन पर उम्मीदवार चयन में भारी अव्यवस्था का आरोप लगाया। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कई मौजूदा विधायक और पूर्व सांसदों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी शिकायतें नहीं सुनी गई तो वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरेंगे।

आंतरिक संकट ने एनडीए के राज्य और केन्द्रीय नेतृत्व, दोनों को हिला कर रख दिया है। महागठबंधन की बढ़ती गति का मुकाबला करने की उम्मीद कर रहे एनडीए को अब विद्रोह रोकने, नाराज सहयोगियों को मनाने और जन छवि सुधारने जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह बगावत एनडीए के भीतर चुनावी संभावनाओं को लेकर गहरी बेचैनी को दर्शाती है। एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, गठबंधन में घबराहट के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। आंतरिक दरारों ने इसकी कमजोरी उजागर कर दी है।

मतदान में अब एक महीने से भी कम समय बचा है और एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष से नहीं, बल्कि अपने ही घर के भीतर से उभर रही है।

तेजस्वी यादव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 17 सीटें जीत पाई थी। इस खराब प्रदर्शन के कारण ही, महागठबंधन सरकार नहीं बना सका था।

सूत्रों का कहना है कि अदालत द्वारा लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिये जाने के बाद, कांग्रेस, खासतौर से राहुल गांधी और गांधी परिवार, यादव परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे का इस्तेमाल तेजस्वी यादव पर हमला करने के लिए करेगी।

अब सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा और तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में नामित करने का ऐलान पटना में किया जाएगा, क्योंकि तेजस्वी आज देर शाम वापस बिहार रवाना हो गए हैं।

करुर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को रैली के दौरान भगदड़ हुई थी। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 41 लोगों की मृत्यु और 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।

शीर्ष अदालत ने टीवीके और पनीरसेल्वम पिचाईमुथु, एस प्रभाकरन, सेल्वराज पी, जी एस मणि तथा अन्य की याचिकाओं पर अपना यह आदेश पारित किया। याचिकाओं में सीबीआई जांच की मांग की गई थी।

हमास ने बीस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में कम से कम बीस देश भाग ले रहे हैं।

कैदियों की अदला-बदली देखने और इज़रायली संसद को संबोधित करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप मिस्र के इस तटीय शहर पहुंचे, जहाँ वे क्षेत्र में स्थायी शांति लाने के लिए आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में बीस से अधिक देश भाग ले रहे हैं। यह प्रक्रिया निश्चित रूप से लंबी होगी और हर मुद्दे पर सहमति बनाना एक कठिन और समय लेने वाला काम साबित होगा।

तीन विद्वानों को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

था। यह परिवार बहुत मुश्किलों से नाज़ी नरसंहार में बच गया था।

फिलिप अघियन एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री हैं जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्यापन करते रहे हैं।

पीटर होविट कनाडाई अर्थशास्त्री हैं, जो नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त करने के बाद विभिन्न विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908